State agricultural Universities including National Research Institutes, National Research Centres, Project Directorate of different Crops etc. The varieties and technologies so developed are tested at diverse agro-climatic condition before recommending for adoption under specific location. Andhra Pradesh is also covered under these Coordinated Programmes.

(d) and (e) A sum of Rs. 1746.71 lakhs was allocated under AICRP and National Research Centres in Andhra Pradesh during 1997-98.

Outlay on Agricultural Research

2494. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the outlay on agriculture research instead of depending on foreign firms;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the measures initiated to protect the farmers already affected by the multinational companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The Department does not depend on any foreign firm to increase the outlay on agricultural research. However, the Department has proposed to the Planning Commission and Ministry of Finance for increase in the outlay on agricultural research to the tune of 1% of Agricultural Gross Domestic Product. Presently, the Department is investing about 0.6% of Agricultural GDP on agricultural research.

(c) The question does not arise.

उर्वरकों की खरीद में कमी

2495. **श्री रमा शंकर कौशिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि से किसानों द्वारा उर्वरकों की खरीद में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव रबी की फसल पर नही पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो निचले और माध्यम वर्ग के किसानों को उर्वरकों खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) और (ख) यूरिया का मूल्य 29.1.99 से 340 रु0 प्रति मीटरी टन बढ़ा दिया गया था । किसी माह विशेष में उर्वरकों की बिक्री इसके मूल्य सहित बहुत से कारकों पर निर्भर करती है । हालांकि फरवरी, 1999 के दौरान यूरिया की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, फिर भी फरवरी, 1999 के अंत तक रबी की कुल बिक्री 85.97 लाख मी0 टन0 थी । जबकि पिछले रबी की इसी अवधि के दौरान 83.24 लाख मी0 टन थी । अतः यूरिया के मूल्य में वृद्धि से मौजूदा रबी फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है ।

(ग) यूरिया के मूल्य में हाल की वृद्धि के पश्चात भी यूरिया तथा फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर सभी वर्गो के किसानों के लिये अत्याधिक राजसहायता दी जा रही है ।

प्याज का प्रत्याशित उत्पादन

2496. **श्री रमा शंकर कौशिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किसानों से प्याज की नई फसल खरीदने का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 1999 के दौरान राज्य-वार का अनुमानतः कुल कितना उत्पादन होगा;

(ग) क्या गत वर्ष के प्याज संकट को देखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 1999 के लिए घरेलू खपत हेतु प्याज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित कर लिया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्याज के निर्यात के पुनः आदेश जारी किए गए है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार को मंडी हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत प्याज की खरीद के लिए किसी भी राज्य से प्रस्ताव नही मिला है ।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान प्याज के प्रत्याशित राज्य वार उत्पादन का विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**) ।

(ग) भारत सरकार की प्याज के भण्डारण की कोई स्कीम नही है ।

(घ) और (ड) प्याज के निर्यात पर लगी रोक पहली फरवरी, 1999 के आंशिक रूप से हटा ली गई थी और बंगलौर के रोज प्याज तथा कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई । दोनों सरकारों द्वारा श्रीलंका को 3000 मी. टन प्याज के निर्यात की पारस्पारिक अनुमति

भी दी गई । मण्डी में प्याज की सरल सुलभता तथा गिरते मूल्यों को देखते हुए 12 फरवरी, 1999 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामजद की जाने वाली एजेन्सियों के जरिए तीन माह के लिये प्रतिमाह 25,000 मीटरी टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया गया । इसके अलावा, 5 मार्च,1999 को गुजरात सरकार द्वारा नामजद एक एजेंन्सी को 15,000 मीटरी टन प्याज निर्यात तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को प्रतिमाह 10,000 मीटरी टन प्याज निर्यात करने की अनुमति तीन माह (मई, 1999 तक) के लिए देने का निर्णय भी लिया गया ।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान प्याज का राज्यवार प्रत्याशित उत्पादन

(लाख मीटरी टन में)

	राज्य	उत्पादन
1.	आंध्र प्रदेश	2.95
2.	बिहार	1.60
3.	गुजरात	6.28
4.	हरियाणा	0.95
5.	कर्नाटक	4.55
6.	मध्य प्रदेश	2.30
7.	महाराष्ट्र	12.40
8.	उडीसा	3.23
9.	राजस्थान	3.35
10.	तमिलनाडु	3.05
11.	उत्तर प्रदेश	4.85
12.	अन्य	1.73
	योग	47.24

Procuring foodgrains for Central and State Stocks

2497; SHRI AKHILESH DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the estimated foodgrain production of rabi crops this year, indicating also the total foodgrain production for the current year;

(b) the comparative figures for the past two years; and

(c) the quantum of foodgrains procured by Government for the Central and State stocks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The estimated foodgrains production season-wise for the current year and the last two years is given below:

(million tonnes)

Season	1996-97	1997-98	1998-99
Kharif Foodgrains	103.92	101.13	98.70
Rabi Foodgrains	95.52	91.30	96.55
TOTAL	199.44	192.43	195.25

(c) A quantity of 22.41 million tonnes of foodgrains has been procured by the government for the central and state stock during 1998-99, as on 12-03.99.

Jabalpur Quake Fund

2498. SHRI AKHILESH DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Comptroller and Auditor General has in a recent report revealed misappropriation of crores of rupees from the Jabalpur Quake (of May, 22 1997) Fund;

(b) if so, details of the financial irregularities and the amount misspent from the said quake fund indicating the total quake relief fund given by the Central Government; and

(c) the steps taken in the light of the CAG's report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1997-98 is awaited.

(b) and (c) Do not arise.

Dairy Farming Cooperative Societies

2499. SHRI LAJPAT RAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Government have any programme to set up the dairy farming cooperative societies in the urban areas of Punjab where these are non-existent for supplying pure milk and dairy products in these areas at reasonable prices;